आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास सांविधानिक हों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। - बाल गंगाधर तिलक

उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के पटना में बढ़ते तापमान और लू से पिछले कुछ दिनों से हो रही मौतें ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती के बारे में ही बताती हैं। तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि से हर साल मौत के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिससे चिकित्सा तंत्र पर दबाव बढ़ा है।

गर्मी से मौतें

बढ़ते तापमान और लू के कारण उत्तर प्रदेश व बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लोग मारे जा रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक है। गर्मी और लू से अकेले उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अस्पताल में 10 से 17 जून के बीच 121 मौतें हुईं, जिनमें से 34 मौतें तो बाद के दो दिनों में हुईं। वहां औसत तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और तमाम अस्पताल डायरिया व लू के मरीजों से भरे हुए हैं। बताया जाता है कि मृतकों में ज्यादातर लोग न सिर्फ औसतन साठ से अधिक की उम्र के थे, बल्कि वे सभी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। अत्यधिक गर्मी से उनकी स्थिति खराब हुई और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और डायरिया आदि से मौतें हुईं। कहा जा रहा है कि कोरोना काल में भी बलिया में मौत का ऐसा तांडव नहीं हुआ था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बलिया भेजकर और गर्मी व लू की चुनौती को देखते हुए जिला अस्पताल में विशेष वार्ड बनाकर स्थिति संभालने की कोशिश हुई है। बिहार के पटना में भी अत्यधिक गर्मी और लू से हुई मौतों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस कारण बिहार में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में पांचवीं तक के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने तापमान घटने की संभावना तो नहीं ही जताई है, उल्टे अगले पांच दिन तक विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तापमान और बढ़ने की बात कही है। ग्लोबल वार्मिंग से भारत समेत पूरी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने के अलावा बीमारियां बढ़ रही हैं और कामकाज प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक, वर्ष 2000 से 2004 तक देश में लू और बढ़े तापमान के कारण सालाना औसतन 20,000 मौतें होती थीं, पर वर्ष 2017 से 2021 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर सालाना 31,000 मौतों का हो गया। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक समस्या है और इससे एकजुट होकर ही निपटा जा सकता है। पर बढ़ते तापमान से मुकाबले के लिए

अहमदाबाद में शुरू किए गए हीट ऐक्शन प्लान का अनेक शहरों में जिस तरह पालन हो रहा है, जिसके तहत कम आय वाले लोगों के घरों व बस्तियों में टीन या लोहे की चादर वाली छतें हटाकर कूल रूफ की व्यवस्था की जाती है, वह बताता है कि मौलिक उपायों के जरिये ही लू से निपटा जा सकता है। हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए लू से बचाव संभव नहीं है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की कीमत गरीब तबका ही ज्यादा चुका रहा है।

करीब आते भारत-ऑस्ट्रेलिया

चीन से तनाव ने पहले ऑस्ट्रेलिया को भारत से जोड़ा, फिर सीमा पर भारत-चीन के सैनिकों की हिंसक भिड़ंत के बाद नई दिल्ली ने भी कैनबरा को महत्व देना शुरू किया, जिसमें क्वाड सहायक साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की डीकेन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी होने वाली है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्ते के बारे में लंबे समय तक माना जाता रहा कि स्वाभाविक दोस्ती के बावजूद आपसी रिश्ते उपेक्षित हैं। दोस्ती को स्वाभाविक इसलिए माना गया कि इनका औपनिवेशिक इतिहास एक ही होने के कारण इनके लोकतांत्रिक मूल्य व सांस्कृतिक लक्ष्य कमोबेश एक ही हैं। इसके बावजूद साझा रिश्ते उपेक्षित रहे, क्योंकि शीतयुद्ध के दौरान भारत को उसकी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ओर ले गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका से मजबूत रिश्ते रहे।

यह कहना सही नहीं कि 'तीन सी-यानी करी, क्रिकेट और कॉमनवेल्थ' भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के आधार हैं। सच तो यह है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया पहले ब्रिटिश साम्राज्य का, फिर अमेरिकी जीवन मूल्यों का वाहक रहा। भारत न केवल पदानुक्रम से विकसित इन राजनीतिक और आर्थिक विश्व व्यवस्था का विरोधी व आलोचक रहा, बल्कि यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्देशित भारतीय संस्कृति के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रचार-प्रसार में भरोसा करता रहा। ऑस्ट्रेलिया शीतयुद्ध के बाद अमेरिका से जुड़ा रहा, जबकि भारत की विदेश नीति उसकी रणनीतिक जरूरतों से चालित रही।

प्रिया चाको

भारत ने हालांकि 1990 के दशक में उदार अर्थनीति अपनाई, लेकिन इसका आर्थिक विकास मुख्यतः सेवा क्षेत्र के प्रसार पर आधारित रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति खासकर चीन को संसाधनों और शैक्षिक सेवाओं के निर्यात पर केंद्रित रही। ऐसे में, भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहतर रिश्ते स्थापित करने के लिए आर्थिक कारण कम थे।

पिछले पांच साल में अलबत्ता चीन से तनाव बढ़ने के कारण स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। चीन से ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते वर्ष 2017 में बिगड़ने शुरू हुए। ऑस्ट्रेलिया और खासकर प्रशांत क्षेत्र में, जिसे कैनबरा अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है, चीन के बढ़ते हस्तक्षेप से ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ

बहुत परेशान हुआ, बल्कि नीति-नियंताओं को इससे खतरा भी महसूस हुआ। नतीजतन चीनी दखल को रोकने और चीनी निवेश पर अंकुश लगाने के लिए आनन-फानन में वहां ऐसे सख्त सुरक्षा कानून बने, जिससे नागरिक अधिकारों का भी हनन हुआ।

यही नहीं, ऐसे में, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत तो किए ही, उसे जापान और भारत जैसे देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस हुई। ऑस्ट्रेलिया की बेरुखी देखकर चीन ने कैनबरा की पूर्ववर्ती लिबरल-नेशनल गठबंधन सरकार पर रणनीतिक प्रतिबंध जैसी स्थिति आयद की, कुछ ऑस्ट्रेलियाई कृषि उत्पादों और दूसरी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया तथा अपने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने के प्रति हतोत्साहित करने की नीति अपनाई। ऐसे में, ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी वस्तुओं के लिए चीन से इतर बाजार ढूंढने की जरूरत महसूस हुई।

वर्ष 2020 में चीन से भारत के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि वर्ष 1975 के बाद पहली बार सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई, जिसमें मौतें भी हुईं। वर्ष 2021 और 2022 में भी दोनों के बीच झड़प हुई और कई दौर की वार्ताओं से भी हल नहीं निकला। नतीजतन भारत ने जहां उपभोक्ता वस्तुओं और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए आवश्यक उपादानों के चीन से आयात कम या खत्म करने के लिए स्थानीय उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहन देना शुरू किया, वहीं चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क थोपने तथा प्रतिबंध लगाने, कुछ चीनी तकनीकों को अपने यहां प्रतिबंधित करने और चीनी निवेश पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

ऐसे में, वर्ष 2020 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बेहतर और मजबूत होने शुरू हुए। उसी साल दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, और ऑस्ट्रेलिया आखिरकार मालाबार सैन्याभ्यास में शामिल हुआ, जिसकी इस साल वह मेजबानी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने का आकांक्षी था, अब भारत भी इस क्षेत्र में पहल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों के भारत दौरे को देखते हुए पिछले साल भारतीय मंत्री भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए। अब क्वाड दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों का मंच बना है। हालांकि पहले क्वाड के मंच से भी चीन का उल्लेख करने से भारत बचता था, लेकिन 2021 से वह दक्षिण और पूर्व चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों का उल्लेख करता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपना साझेदार मानते हुए सेमी कंडक्टर्स की आपूर्ति करने का भरोसा दिया है, तो मेडिकल उपकरणों और टीकों के क्षेत्र में दोनों देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

दोनों देशों में नागरिकों की आवाजाही भी बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासन और अध्ययन के लिए हर साल पहुंचने वाले विदेशियों में भारत का स्थान दूसरा है। इसी तरह डीकेन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी होने वाली है। छात्रों, शोधार्थियों, स्नातकों और कारोबारियों-उद्योगपतियों की अबाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दोनों देश एक समझौते पर दस्तखत करने जा रहे हैं।

दोतरफा रिश्तों में हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उन्नत हथियारों के लिए रूस पर भारतीय निर्भरता को देखते हुए इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए संभावना उतनी नहीं है, क्योंकि मास्को और कैनबरा के बीच भरोसे का रिश्ता भी नहीं है। ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन पर हमले के कारण रूस वैश्विक आलोचना के केंद्र में है, लेकिन भारत ने उसके साथ पहले जैसे रिश्ते बना रखे हैं। फिर भारत द्वारा ऑस्ट्रेलियाई कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार न खोलने तथा ऑस्ट्रेलिया का भारतीय श्रमिकों के प्रति उदार नीति न अपनाने के कारण भी कुछ बाधाएं बरकरार हैं।

इसके बावजूद शीर्ष स्तर पर दोतरफा रिश्ते मजबूत और संभावनाओं से भरपूर हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी के कैनबरा दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने जहां भारत की आंतरिक स्थिति पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया, वहीं ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों के संदर्भ में मोदी ने कहा कि इस बारे में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से यह भरोसा मिला है कि भारत-विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इन सबसे यह संकेत मिलता है कि आगामी दिनों में दोतरफा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे।

-लेखिका एडिलेड यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर हैं।

डॉ. राधाकृष्णन (1888-1975)

आजादी के अमृत कथन

हर इंसान में एक ही तरह की प्रेरणा होती है और इसलिए वह हमारे प्यार, हमारे सम्मान का हकदार है। समाज का निरंतर प्रयास रहा है कि वह अन्य प्राणियों के साथ सद्भाव से रहे।

आत्मा की अनदेखी कर हम रचनात्मकता खो देंगे

मित्रो, मेरे विचार से धर्म या सत्य की खोज एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। जब हम ब्रह्मांडीय प्रक्रिया को देखते हैं, तो पाते हैं कि चीजें एक दूसरे के बाद आती हैं; महान सभ्यताएं, कला के महान अवतार—महान चीजें उत्पन्न होती हैं, तेजी से बढ़ती हैं और समाप्त हो जाती हैं। और हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या सभी चीजें समाप्त हो रही हैं या कोई ऐसी भी चीज है, जो नहीं मिटती? क्या ऐसा कुछ है, जिसे परिवर्तन की इस निरंतर प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय माना जा सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसे हर चिंतनशील व्यक्ति को उठाना पड़ता है। वह यह नहीं सोच सकता कि मात्र विनाश ही सारे अस्तित्व का अंत है। इसी तरह, बुद्ध ने प्रश्न उठाया, 'बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, यही सब है या इनके पार भी कुछ है? इसी तरह, ईसाई धर्मोपदेश का कहना है, मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं है। यानी कुछ तो है, जो मौत के बाद भी बच जाता है। यदि जीवन का महत्व है, यदि इसका कोई अर्थ है, इसका कोई उद्देश्य है, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, जो समय का अतिक्रमण करे, जो मृत्यु से मुक्त हो, और जो हमें यह महसूस कराए कि सभी में एक अमर तत्व है।

मनुष्य को समझना होगा कि ईश्वर कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि उसके भीतर है। मनुष्य ही इस दुनिया को बेहतर बना सकता है, क्योंकि वह परमात्मा की छवि है। जब तक वह सही काम करेगा, तब तक प्रगति करेगा।

धर्म की वास्तविक गुणवत्ता हमारी सतत व अटूट खोज, चीजों की सच्चाई जानने और इस दुनिया में दया बढ़ाने के लिए सामने आती है। खोज की तीव्रता और उन चीजों का विस्तार, जिनसे हम प्यार करते हैं, ये एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के दो पहलू हैं। हमें सत्य की इस खोज को तब तक जारी रखना चाहिए, जब तक कि हम इसे खोजने में सक्षम न हो जाएं, इसे आमने-सामने न देख लें। और जो भी हो, हर इंसान में एक ही तरह की प्रेरणा होती है और इसलिए वह हमारे प्यार, हमारे सम्मान का हकदार है। सभी सभ्यताओं में समाज का निरंतर प्रयास रहा है कि वह अन्य प्राणियों के साथ सद्भाव से रहे। हम इस प्रयास को बनाए रखते हैं। हम तब तक प्रयास करते रहते हैं, जब तक कि सारा संसार हमारा अपना परिवार, हमारा अपना देश न बन जाए।

सत्य यह है कि मनुष्य में अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने की क्षमता है, स्वयं से ऊपर उठने और स्वयं को परिपूर्ण करने की क्षमता है। यह परिपूर्णता एक व्यर्थ सपना नहीं है, यह कुछ ऐसा है, जिसे प्रयास करने से साकार किया जा सकता है। यदि हम आत्मा की अनदेखी कर देते हैं, तो वस्तुओं, विचारों और अमूर्तताओं से बंध जाएंगे। हम मनुष्य की वास्तविक रचनात्मकता को खो देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे जो भी हों, आपको उस जीवित आत्मा का एहसास होना चाहिए, जो आपके भीतर है। समाज में किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गरीबी, बीमारी और अज्ञानता का सामना नहीं करना चाहिए। यदि हम इन भावनाओं के प्रति सच्चे हैं, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था में यह दिखना चाहिए।

पिछले दो हजार साल से ऐसा कोई दशक नहीं रहा, जब इस दुनिया में सैन्य संघर्ष नहीं हुआ हो। और आज भी, यह हो रहा है। कोई भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। मनुष्य को समझना होगा कि ईश्वर कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि उसके भीतर है। मनुष्य के लिए ही इस दुनिया को बेहतर बनाना संभव है, क्योंकि वह परमात्मा की छवि है। इसलिए जब तक वह सही काम करेगा, तब तक प्रगति करेगा और वही मौजूदा स्थिति से बेहतर भविष्य बना सकता है।

-भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में 20 अक्तूबर, 1965 को दिए भाषण के संपादित अंश।

दूसरा पहलू

ग्वाटेमाला राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी कर रहा है, लेकिन नागरिक अधिकार समूहों का कहना है कि वह पहले ही कलंकित हो चुका है।

भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला ही जेल में

ग्वाटेमाला के सबसे हाई-प्रोफाइल पत्रकारों में से एक को बुधवार यानी 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया और छह साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारों ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानून के राज की बिगड़ती स्थिति का संकेत है। पत्रकार जोस रूबेन जमोरा पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया गया। अभियोजकों का कहना है कि उनका ध्यान पत्रकारिता पर नहीं, बल्कि सौदेबाजी पर था। जमोरा ग्वाटेमाला के एक प्रमुख समाचार पत्र *एलपेरियोडिको* के संस्थापक और प्रकाशक थे, जो नियमित रूप से सरकारी भ्रष्टाचार का खुलासा करता था, जिसके निशाने पर वर्तमान राष्ट्रपति ऐलेजैंड्रो जियाम्माटेई और अटॉर्नी जनरल मारिया कंसुएलो पोरस भी थीं।

एमिलियानो रोड्रिग्ज मेगा

ग्वाटेमाला में 2021 से करीब तीन दर्जन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार-विरोधी अभियोजक और उनके वकील देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 22 पत्रकारों को धमकाया गया।

ग्वाटेमाला में प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह फैसला देश के लड़खड़ाते लोकतांत्रिक सेहत के लिए एक और झटका है, क्योंकि सरकार और उसके सहयोगियों ने प्रमुख संस्थानों और स्वतंत्र समाचार पत्रों पर बार-बार निशाना साधा है। वहीं 66 वर्षीय जमोरा ने कुछ भी गलत करने से इन्कार किया और सरकार पर अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

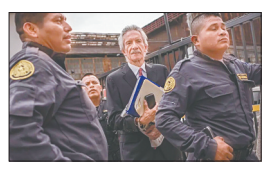

जनवरी, 2020 में राष्ट्रपति जियाम्माटेई के कार्यभार संभालने के बाद से ग्वाटेमाला के पत्रकार संघ ने प्रेस के खिलाफ उत्पीड़न, शारीरिक हमलों, धमकी और प्रतिबंध के 472 मामलों का दस्तावेज तैयार किया है।

वाशिंगटन स्थित शोध संस्थान 'वोला' की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन सरकार को चुनौती देने वाले लोगों को निशाना बनाने के लिए न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहा है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के मामले रोक दिए गए हैं और न्याय प्रणाली को भ्रष्ट नेताओं के नेटवर्क द्वारा 'अपहृत' कर लिया गया है। वहां 2021 से करीब तीन दर्जन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार-विरोधी अभियोजक और उनके वकील देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 22 पत्रकारों का कहना है कि उन्हें उनके काम के कारण धमकाया गया। देश 25 जून को राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी कर रहा है, लेकिन नागरिक अधिकार समूहों का कहना है कि वह पहले ही कलंकित हो चुका है। जनवरी, 2020 में राष्ट्रपति जियाम्माटेई के कार्यभार संभालने के बाद से ग्वाटेमाला के पत्रकार संघ ने प्रेस के खिलाफ उत्पीड़न, शारीरिक हमलों, धमकी और प्रतिबंध के 472 मामलों का दस्तावेज तैयार किया है। बुधवार को जमोरा ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और अपने मामले को मानवाधिकारों के अंतर-अमेरिकी न्यायालय में ले जाएंगे, जो अमेरिकी प्रांतों के संगठन का हिस्सा है। *-साथ में जोडी गार्सिया।*

©The New York Times 2023

आंकड़े

बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में कुल वाहन पंजीकरण का 6.4 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का है।

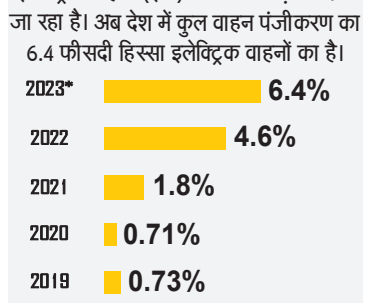

*आंकड़े 15 जून तक हैं। | स्रोत : Vahan Registration; RBI

प्रचुर भोजन करने से उत्पन्न आलस्य व निद्रा, भोग व अनंत इच्छाओं की कामना, शारीरिक श्रम का अभाव-ये सब रोग पनपने के कारण हैं।

संयम से स्वास्थ्य

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

भगवान बुद्ध श्रावस्ती के निकट एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति उनके दर्शन के लिए पहुंचा। बेडौल शरीर के कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसने खड़े-खड़े विनम्रता से कहा, 'भगवन, मेरा शरीर अनेक व्याधियों का अड्डा है। रात को न नींद आ पाती है और न दिन में चैन से बैठ पाता हूं। मुझे रोगमुक्ति का साधन बताने की अनुकंपा करें।'

भगवान बुद्ध ने कहा, 'प्रचुर भोजन करने से उत्पन्न आलस्य व निद्रा, भोग व अनंत इच्छाओं की कामना, शारीरिक श्रम का अभाव-ये सब रोग पनपने के कारण हैं। जीभ पर नियंत्रण रखने, संयमपूर्ण सादा सात्विक भोजन करने, शारीरिक श्रम करने, और अपनी इच्छाएं सीमित करने से ये रोग स्वतः विदा होने लगते हैं। असीमित इच्छाएं और अपेक्षाएं शरीर को घुन की तरह जर्जर बना डालती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें त्यागो।' सेठ ने उनके वचनों का पालन करने का संकल्प लिया और लौट गया। एक महीने में ही वह स्वस्थ हो गया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, 'शरीर का रोग तो दूर हो गया। अब चित्त का प्रबोधन कैसे हो।'

बुद्ध ने कहा, 'विचारों का संयम चित्त को शांति और संतोष देगा।'

सेठ बुद्ध के बताए मार्गों पर चलने लगा, फिर जल्दी ही उसे लाभ नजर आने लगा।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 15 अप्रैल, 1963

म्यांमार ने दी विदेशी बैंकों को राहत

बर्मा की बारह विदेशी बैंकों को सुविधा
मूल पूंजी वापस ले जाने की अनुमति
रंगून, १३ अप्रैल। बर्मा की क्रांतिकारी सरकार ने १४ में से १२ विदेशी बैंकों को अपनी मूल पूंजी प्रधान कार्यालयों को वापस करने का आदेश दे दिया है।
दो बैंकों स्टेट बैंक आफ इंडिया व सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को अभी यह अनुमति नहीं दी गई है।

म्यांमार (बर्मा) की क्रांतिकारी सरकार ने 14 में से 12 विदेशी बैंकों को अपनी मूल पूंजी वापस ले जाने की अनुमति दी है। दो बैंकों-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को यह अनुमति नहीं दी गई है। उनके खातों की अभी जांच हो रही है।

महंगाई घटने से विकास को गति

महंगाई का जीडीपी वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब महंगाई में गिरावट आने से उम्मीद है कि भारत की विकास दर में और तेजी आएगी।

सतीश सिंह | अर्थव्यवस्था

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति मई में 4.25 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि अप्रैल में यह 4.7 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष मई में यह 7.04 प्रतिशत थी। यह लगातार चौथा महीना है, जब खुदरा महंगाई में कमी आई है। और यह लगातार तीसरा महीना है, जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महंगाई की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत से कम है।

खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमत में कमी आने से महंगाई में कमी आई है। महंगाई का सीधा संबंध इंसान की खरीदने की क्षमता से है। जैसे, यदि महंगाई दर 10 प्रतिशत है, तो आपको अपनी 100 रुपये की कमाई में से 10 रुपये सिर्फ वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमत की वजह से ज्यादा खर्च करने होंगे। महंगाई के कम होने का सकारात्मक परिणाम औद्योगिक उत्पादन पर दिख रहा है।

अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन 4.2 प्रतिशत रहा, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 6.7 प्रतिशत बढ़ा है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 4.9 प्रतिशत और खनन में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, बिजली उत्पादन में 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

महंगाई में नरमी आने से केंद्रीय बैंक ने ताजा मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, जबकि पिछले साल के मई महीने से अब तक रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। रिजर्व बैंक के इस फैसले को अप्रत्याशित माना जा रहा है, क्योंकि हाल में दुनिया के तमाम केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों में इजाफा किया था। रेपो दर को यथावत रखने से जहां कर्जदारों को राहत मिलेगी, वहीं विकास की रफ्तार तेज होगी। रिजर्व बैंक चाहता है कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी में और भी तेजी आए। रेपो दर में इजाफा न होने से बैंकों के शेयर में भी तेजी देखी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, पर अर्थव्यवस्था पर उसका नकारात्मक प्रभाव लगभग न के बराबर पड़ेगा।

अभी रिजर्व बैंक का लक्ष्य विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाना है, ताकि आम आदमी को परेशानी न हो और विकास की रफ्तार में भी तेजी आए। रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार, कोरोना महामारी, भू-राजनीतिक संकट, महंगाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान भारत में मजबूत बने हुए हैं।

बीते महीनों में महंगाई में उल्लेखनीय कमी आने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.1 प्रतिशत रही, जबकि दिसंबर, 2022 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में जीडीपी के 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में बेहतरी होने से पूरे वित्त वर्ष की वृद्धि दर में सुधार दर्ज किया गया। पहले वित्त वर्ष 2022-23 में एमपीसी ने जीडीपी के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, जो हकीकत में 7.2 प्रतिशत रही।

कृषि, होटल उद्योग और निर्माण क्षेत्र ने जीडीपी की वृद्धि दर को बेहतर करने में विशेष योगदान दिया है। जीडीपी में वृद्धि के साथ-साथ निवेश और खपत में भी तेजी देखी जा रही है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही में निवेश दर में 18.3 प्रतिशत और खपत में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निवेश में वृद्धि का मुख्य कारण सरकार की 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' (पीएलआई) योजना है। इसकी वजह से कोरोना काल में कारोबारियों को मुश्किल दौर से बाहर निकलने में विशेष मदद मिली थी।

साफ है कि महंगाई की वजह से जीडीपी वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीते वर्षों में महंगाई लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई थी, पर अब उसमें गिरावट आ रही है। लिहाजा, उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी महीनों में भारत की विकास दर में और भी तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था भी क्रमशः मजबूत होती जाएगी।

edit@amarujala.com